(b) It is not possible to indicate any target date for the implementation of all the recommendations.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसको कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वह इसको कार्यान्वित नहीं करना चाहती हैं ? वे कौन से कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें कार्यान्वित न करने के चाहने का प्रश्न नहीं है। इसमें अधिकतर जो शिफारिशें थीं उनको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन कुछ शिफारिशें ऐसी हैं-मस्लन एक सिफारिस खोसला कमीशन की यह थी कि कमिश्नर आफ पुलिस यहां बनाया जाये जिस पर बाद में ला कमीशन ने भी अपनी कुछ राय दी है और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर ने भी अपनी राय दी है। इसलिए अब इन तीनों—पुलिस कमीशन, ला कमीशन और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर -- की रायों को इकट्ठा करके विचार किया जा रहा है। इसमें इस तरह की चीजें भी हैं जिन पर फौरन कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक निर्णय हो जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, खोसला कमीशन ने पुलिसमेन की वर्किंग कंडीशन्स के बारे में भी सुझाव दिये थे। मंत्री महोदय ने यहां पर पुलिस कमिश्नर की बात कहकर बरगलाने की कोशिश की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिसमेन की वर्किंग कंडीशन्स के बारे में खोसला कमीशन ने जो सुझाव दिये थे उनको क्या आपने पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया है या नहीं ? अगर नहीं किया है तो उसके क्या कारण हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कौन सी बात सोच रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, मैं ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में कई मुद्दे रखे गये है—कंडीशन्स आफ सर्विस, पे ऐन्ड एलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज एजूकेशनल फैसिलिटीज, रेक्रूटमेंट एंड प्रमोशन—इन सब शिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है वह सब उसमें दिया है। अगर माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे तो उनको अन्दाजा हो जायेगा कि कमीशन की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री रामचंद्र विकल : क्या माननीय गृह मन्त्री बतायेंगे कि यह आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ और क्या कुछ ऐसी भी संस्तुतियां इसके अन्दर हैं जिनको सरकार कार्यान्वित करने में असमर्थ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि कमिश्नर आफ पुलिस का मामला ऐसा है जिस पर अलग-अलग रायें हैं—ला कमीशन की राय अलग है, पुलिस कमीशन की राय अलग है—तो इस तरह की चीज में यह कहना कि फलां तारीख तक कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि हाउसिंग का एक निश्चित प्रतिशत कब तक बढ़ जायेगा। इसमें इन्सपेक्टर से लेकर कांस्टेबिल तक के लिए योजनायें बनाई गई और उसके अनुसार खर्चा भी किया गया, मकान भी बने लेकिन इसी बीच पुलिस में भर्ती बढ़ गई और उसकी वजह से हाउसिंह का प्रतिशत जो कि ऊंचा आ रहा था वह फिर नीचा हो गया। तो इस तरह के सवालों में निश्चित समय निर्धारित करना मुश्किल होगा।

Formation of Inter-State Council

+
*71. SHRI KALYANASUNDARAM ;
SHRI B. S. BHAURA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission's recommendation regarding

the setting up of an Inter-State Council to discuss issues of national importance has been considered by Government ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (*GRIH MANTRALAYA AUR KARMIK VIBHAGMEN RAJYA MANTRI*) (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b). The relevant recommendations of the Administrative Reforms Commission are nder examination.

SHRI KALYANASUNDARAM : How long has this question been under consideration and when will a decision be taken in the matter as it relates to an important question concerning the nation as a whole.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : The report of the Administrative Reforms Commission on Centre-State relations was submitted in June 1969. It contains very important and complicated recommendations which need to be thoroughly examined and many ministries have to be consulted ; the State Governments may also to be consulted. That is why it is taking a long time ; it is hoped that very soon we shall be able to complete the processing of the recommendations.

SHRI KALYANASUNDARAM : May I know whether the Government have taken steps to ascertain the views of the State Governments ? Which are the State Governments which have sent their replies ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : There are many recommendations in this report—not merely about the inter State Councils about which this question is concerned. It contains recommendations regarding the role of Governors, inter-State water disputes, problem of law and order, procedure for appointment of High Court Judges and so on. It is not clear which particular recommendation the hon. Member has in view. Where necessary the State Governments would certainly be consulted.

SHRI B. S. BHAURA : This ecommendation is based on the constitutional r ovision. What are the factors preventing the Government from implementing this recommendation ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : The Constitution does make a reference to the establishment of inter-State Councils by the President when he thinks appropriate. The recommendation of the A.R.C. in its report is that such councils should be constituted under the provisions of the Constitution. So it is true that whatever has been recommended is covered by the provisions of the Constitution. At what stage and under what circumstances and in what context this provision of the Constitution has to be brought into effect—these are matters for consideration by the President.

श्री आर० बी० बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि जैसे यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन की रिपोर्ट आई है क्या वैसे ही राज्यों में भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन ने इस पर विचार किया है जैसे कि मध्यप्रदेश में मिस्टर दीक्षित की अध्यक्षता में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन बना हुआ है तो क्या उन के ध्यान में इसे लाया जायेगा ? क्या उसके लिए आप विचार करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह सही है कि कई राज्यों में प्रशासनिक सुधार आयोग व कमेटियां बनाई हैं। मध्यप्रदेश के लिए मैं नहीं कह सकता। वहां पर जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने इंटर स्टेट कौंसिल के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। अगर इस प्रकार के कुछ सुझाव वहां के कमिशन की तरफ से दिए गए हैं तो उन पर भी अवश्य विचार किया जाएगा।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH ; May I know whether the setting up of an Inter-State Council in consonance with the cotstitutional provisions is often mixed up with the demand for giving more autonomous powers to State Governments, and has the recent statement of the Chief Minister of Tamil Nadu that he will seek the co-operation of other Chief ministers for getting more powers for making the States more autonomous has this move anything to do with the setting up-of an Inter-State Council, or, it is only a question of placing on a formal footing the provisions that have been enshrined in

our Constitution with regard to Centre-State relationship ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : The Inter-State Council as contemplated under the Constitution is actually a co-ordinating body. It will investigate certain matters and enquire into certain aspects and then make recommendations. I do not think any mandatory powers of arbitration are contemplated under the Constitution. Therefore, the question whether anything could be said about these things does not arise. The concept under the Constitution for an Inter-State Council is very clear, and it is more or less a co-ordinating and advisory body.

Reinstatement of Delhi Policemen Suspended/Dismissed during 1967 Agitation

*72. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Police personnel, who participated in the Dethi Police agitation in 1967 and were dismissed or suspended, have since been reinstated and given full pay for the entire period of their dismissal or suspension; and

(b) if not, the reasons for not implementing Government's announcement in Lok Sabha in that regard in full and the time by which Government propose to implement the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Government announcement with regard to the reinstatement of the dismissed/suspended police personnel can be summarised as follows :—

(i) 717 persons under suspension will be reinstated in the Delhi Police;

(ii) 165 temporary persons whose services were terminated will be taken in the Delhi Police as fresh entrants; and

(iii) 62 persons dismissed for misconduct during suspension will be found fresh employment in other Central Police formations ; but one similarly dismissed lady employee will be obsorbed in the Delhi Police.

In pursuance of this announcement, 717 persons under suspension have been reinstated.

153 persons of the second category have been taken in the Delhi Police and orders of appointment of other 9 persons are being issued. Three persons have not turned up so far.

As regards the third category, 9 persons including the lady employee have been reinstated while orders of appointment of 52 persons in the Central Reserve Police and the Border Security Force are being issued. While checking individual cases, it was found that out of these 63 persons, two persons had been dismissed for reasons not connected with the agitation.

As regards allowances during the suspension period, the suspended men have been paid according to rules, namely, at 50% of the pay for the first year and 75% for the remaining period.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि दिल्ली पुलिस कर्मचारी संघ ने जिन 717 मुअत्तिल पुलिस वालों को अब बहाल कर दिया गया है उनकी सर्विस कटिन्यूड रहे इसके बारे में कोई पत्राचार या ज्ञापन दिया है, यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि इस चीज के लिए उन्होंने कोई ज्ञापन दिया है या नहीं वैसे ज्ञापन मुझको देते ही रहते हैं लेकिन इसके बारे में मैं इस समय नहीं कह सकता ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किये गये नक्सलवादी

*63. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में कितने नक्सलवादी गिरफ्तार किए गए ;